# मध्यप्रदेश बस आनर्स एसोसिएशन


संतोष पाण्डेय
कार्यकारी अध्यक्ष
मो.नं.: 94254-51379

वीरेन्द्र साहु
उपाध्यक्ष
मो.नं.: 94253-89181

जय कुमार जैन
महामंत्री
मो.नं.: 89594-45511

पता: जय कुमार जैन C/o स्टूडेन्ट ट्रैवल्स, मेन बस स्टेण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) 470002


क्रमांक/ 12 /मार्च / 2026 दिनांक 18.03.2026

प्रति,

माननीय मुख्य मंत्रीजी,
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि दिनांक 28.02.2026 को आपके साथ हुई वार्ता में आपके द्वारा हमारी व्यथा को सहृदय सुनकर, हमारी भावनाओ का मान रखते हुए, आपके द्वारा PPP Mode के अधीन संचालित बसों की समस्त प्रस्तावित प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। जिसके लिए हम सभी बस मालिक गण हृदय से आपके आभारी है। इसी तारतम्य में बस मालिको के द्वारा दिनांक 02.03.2026 को प्रस्तावित हडताल भी स्थगित कर दी थी ।

आज दिनांक 18.03.2026 को दैनिक समाचार पत्र पीपुल्स में PPP Mode के विषय में प्रकाशित समाचार का प्रदेश के हम सभी बस मालिक विरोध करते है, तथा श्रीमान के समक्ष परिवहन मंत्री के इस भ्रामक कथन की स्थिति को श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

इस दैनिक समाचार पत्र में परिवहन मंत्री जी के द्वारा जो कथन किया गया है, वह पूर्ण रूप से निराशा जनक है, तथा यह दर्शाता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी, **(जो हम सभी के अभिरक्षक भी है, तथा हम सभी का ख्याल रखने के जिम्मेदार भी है)** के मुख वचन से निकले वाक्यों की भी उनके समक्ष कोई भी कीमत नहीं है, तथा उनके नाम का सहारा भी लिया जा रहा है।

दैनिक समाचार पत्र पीपुल्स में प्रकाशित समाचार में निम्नलिखित तरह से भ्रम फेलाया गया है :-

1. मध्यप्रदेश में 22 साल से बंद पड़ी राज्य परिवहन की बसें अगले महीने से फिर सड़कों में दौड़ेने लगेंगीं ।

   जबकि राज्य परिवहन के पास कोई भी अपनी बस नहीं है, और न ही खरीदने की कोई योजना है ।

2. दैनिक समाचार पत्र पीपुल्स में प्रकाशित समाचार में यह लेख है कि निजी ऑपरेटर्स ने अपने नुकसान को लेकर आपत्तियां जताई है। प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी मार्गों का सर्वे के बाद परिवहन कंपनियों से सरकार की चर्चा अंतिम दौर में है।

   जबकि जो भी वार्ता माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलने के पूर्व, जो भी हुई थी वह निरर्थक रही थी, उन पर निजी बस मालिको का भरपूर विरोध था, इस कारण ही पुरे प्रदेश के बस मालिक गण दिनांक 02.03.2026 से अनिश्चित कालीन हडताल पर जाने के लिए मजबूर हुए थे ।

   जो माननीय मुख्य मंत्री जी से हुई वार्ता के अधीन श्रीमान के आश्वासन के साथ ही ओचित्यहीन हो गयी थी, तथा उसके उपरान्त कोई बातचीत निजी बस मालिको की एसोसिएशन की नहीं हुई है।

   इसमें वर्णित लेख ***"परिवहन कंपनियों से सरकार की चर्चा अंतिम दौर में है"*** के बारे में हमारा यह कथन है कि यही वह कौन सी कम्पनिया है, जिसे यह कार्य दिया जाने की परिवहन मंत्री जी के द्वारा गुप – चुप वार्ता की जा रही है।

3. दैनिक समाचार पत्र पीपुल्स में प्रकाशित समाचार में यह लेख है कि, विभागीय सूत्रों का कहना है कि सभी स्तर पर बातचीत हो चुकी है और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। बसों के संचालन को लेकर निजी बस ऑपरेटर्स ने विभाग के सामने अपनी आशंकाएं और समस्याएं भी रखीं हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर सभी रूट पर ये बसें संचालित की जाएंगी।

   यह स्वयम ही विरोधाभासी है, कि मध्यप्रदेश में 22 साल से बंद पड़ी राज्य परिवहन की बसें अगले महीने से फिर सड़कों में दौड़ेने लगेंगीं तथा दूसरी और यह लेखित है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर सभी रूट पर ये बसें संचालित की जाएंगी।

   आज तक शासन ने खुलकर यह नहीं बताया है कि यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड क्या है तथा वह किस तरह काम करेगा ।

   इस प्रक्रिया में पूर्व से संचालित बस मालिक जो आज परमिट धारी है, उनका भविष्य क्या रहेगा तथा कितना व कितने समय के लिए सुरक्षित रहेगा, या नहीं रहेगा।

4. निश्चित ही वर्तमान बस मालिको को दरकिनार करते हुए यह कार्य किसी मल्टीनेशनल कम्पनी को सोंपा जाने की तैयारी की जाती लगती है, जिसे परिवहन मंत्री के द्वारा छुपाया जा रहा है।

5. जब राज्य परिवहन निगम को घाटे के कारण बंद किया गया था, जिससे शासन का भी अरबो रूपये का टेक्स भी डूबा था, तभी कई नए निजी बस मालिको, निगम के कर्मचारियों को आमंत्रित करते हुए इस व्यवसाय से जोड़ा गया था, जिनके द्वारा वह लोग अपने जीवन की लगभग पूरी जमा पूंजी लगाकर इस व्यवसाय में जुड़े थे, अब उनके सामने यह स्थिति बनाई जाकर जीने – मरने का प्रश्न उत्पन्न किया जा रहा है।

6. दैनिक समाचार पत्र पीपुल्स में प्रकाशित समाचार में यह लेख है कि, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रूट सर्वे से लेकर स्टाफ और एजेंसी आदि की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। निजी बस ऑपरेटर्स से भी चर्चा कर ली है।
   जबकि राज्य परिवहन निगम या शासन की स्वयम की बसें ही नहीं चलाई जायेंगी तो शासन के द्वारा स्टाफ की व्यवस्था क्यों कर ही की जायेगी / की गई है। यह बात भी शंकास्पद है।

7. इस तरह के कथन से पूरे प्रदेश के बस मालिक गण आहत हुए है, तथा श्रीमान से स–सम्मान निवेदन किया जाता है कि मंत्री जी के इस कथन को रोकने की व्यवस्था की जाए, तथा एक विनम्र आग्रह भी है, कि इस व्यवसाय में बहुत कठिनाइयां है, तथा इस कारण इस विभाग का मुखिया भी बदलकर किसी ऐसे व्यक्ति को बनाने की कृपा करें, जो हम बस मालिकों का दुःख, कठिनाई को समझता हो ।

***<u>हम सदा आपके ऋणी व आभारी रहेंगे ।</u>***

सादर धन्यवाद

भवदीय

जय कुमार जैन, महामंत्री